RAJYA SABHA

Friday, the 24th February, 2006/5 Phalguna, 1927 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

MEMBER SWORN

Shri Ongden Tshering Lepcha (Sikkim)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Wheat import

*101. SHRIMATI BRINDA KARAT:††
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC STRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government are planning to import wheat; and

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC STRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): (a) and (b) A Statement is ed on the Table of the House.

श्रीमती वृंदा कारत:सर, यह व्हीट इम्पोर्ट से सम्बन्धित एक बहुत अहम सवाल है। मैंने उस प्रधान मंत्री जी का भी वक्तव्य सुना था और आज मंत्री जी का भी बयान है। श्री शरद जी 3 फरवरी को एक प्रेस स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्हेंने कहा था कि व्हीट इम्पोर्ट की जरूरत ं पड़ती, अगर पी॰डी॰एस॰ में कटौती हो जाती। इस प्रकार तो यह एक अत्यन्त चिन्ता का

---

he question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Brinda Karat.

विषय है। इसलिए मैं यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने क्वैश्चन के आन्सर में जो (i), (iii) और (iv) दिया है, उसमें कहा है कि Lower level of procurement of wheat in 2005-06 in comparison to the offtake. लेकिन सर, जो ऑफटेक के फीगर्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं है। सबसे ज्यादा चिन्ता की बात तो सरकार की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को लेकर है। जब हम फूड सेक्योरिटी का सवाल उठाते हैं, तो यह निश्चित रूप से प्रोक्योरमेंट पर निर्भर है। सर, जो फिगर्स हैं, उनके अनुसार जहां 2002-2003 में 66 मिलियन टन का उत्पादन हुआ, वहाँ 19 मिलियन टन का प्रोक्योरमेंट हुआ अगले साल 72 मिलियन टन्स के उत्पादन में वह प्रोक्योरमेंट नीचे गया और 16.7 टन्स हुआ। उसके बाद पिछले साल में सर, यह प्रोक्योरमेंट गिर कर लगभग 14.78 मिलियन टन्स हुआ। ऐसा जो उन्होंने कहा कि प्रोक्योरमेंट कम हो रहा है, तो मेरा सवाल है कि यह प्रोक्योरमेंट कम क्यों हो रहा है? ...(व्यवधान)...सरकार की यह नीति है कि प्रोक्योरमेंट में सब्सिडी को कम करना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारत: मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार यह स्पष्ट आश्वासन देगी कि जो प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी है, जो फूड सेक्योरिटी का सबसे जबर्दस्त आधार है, उसको कम न करके आप ज्यादा बढ़ाएँगे? इसलिए यह प्रासंगिक है। आपकी सेक्रेटरी ने भी कहा कि ...(व्यवधान)...16 मिलियन टन्स की प्रोक्योरमेंट होगी। कृपया यह बताएँ।

श्री सभापति: जवाब देने दीजिए ना...(व्यवधान)...जवाब देने दीजिए।

श्री शरद पवार: सर, इसमें यह बात सच है कि पिछले साल का जो प्रोडक्शन था, वह इस साल की तुलना में कम था। अगर प्रौडक्शन कम हुआ, तो इसका असर तो प्रोक्योरमेंट पर होता ही है। इसलिए पिछले साल प्रोक्योरमेंट थोड़ा कम हो गया। पिछले साल का प्रोक्योरमेंट 138 लाख टन था और इस साल का अंदाजा 162 के आसपास है। पिछले साल टोटल प्रोक्योरमेंट कम हुआ। पुराने स्टॉक थे, जो कि जिम्मेदारी है। अगला प्रोक्योरमेंट मार्च महीने के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा। तब तक जो अनाज की आवश्यकता है, फूड सेक्योरिटी की जिम्मेदारी है, वह पूरा करने वाला स्टॉक अपने देश में है, गोदामों में है। इसके आगे भी एक महीने का स्टॉक अपने पास है। मगर, बफर स्टॉक पर असर हुआ था। कहीं एक गंभीर संकट आ गया था, तो ऐसे समय पर अपने पास स्टॉक की थोड़ी ज्यादा आवश्यकता थी और वह आवश्यकता पूरी करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़े जहां तक एलोकेशन की बात है, एक बात सच है कि जब यह स्कीम इंटरोड्यूस हुई थी, तब 15 किलो का एलोकेशन था, बाद में 20 कर दिया, 25 कर दिया, 30 कर दिया, 35 कर दिया और जब 30 या 35 कर दिया, तब आवश्यकता नहीं थीं, मगर देश में भंडार इतने भरे थे, जिसे डिस्पोज करने की जिम्मेदारी

सरकार के ऊपर थी। तो वह भंडार खाली करने के लिए कोटा, बढ़ा एलोकेशन बढ़ाया। आज इसकी आवश्यकता नहीं थी, मगर कई राज्यों ने इस बारे में सरकार के सामने सिफारिश की कि इसमें मत करिए और इसलिए राज्य सरकार के साथ बातचीत करके ही हम इसमें अंतिम डिसीजन लेंगे और इसलिए उसको रोका गया।

श्रीमती वृंदा कारत: सभापति जी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है मंत्री का जवाब, जो वह कह रहे हैं कि 35 किलो। जिस देश में इतना व्यापक मालन्यूट्रीशन है, उस देश की सरकार के मंत्री यह कहते हैं कि नहीं, हमें कटौती करने की जरूरत है। सर, यह तो दुर्भाग्यपूर्ण जवाब है। खैर, मेरा जो दूसरा सवाल है, जिसका मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया कि प्रोक्योरमैंट कम क्यों हो रहा है? मैंने बहुत फोकस क्वैश्चन किया कि 90 मिलिटन टन in a drought year, उसको 3 मिलियन कम करके दिया। मेरा जो दूसरा सवाल है, उसका तो जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया। मेरा अगला सवाल है, सर, जो पांच लाख टन ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: पहला ही नहीं दिया, तो दूसरे की क्या जरूरत है?

श्रीमती वृंदा कारत: अब तीसरे की उम्मीद करती हूँ, देखिए वह सही है या नहीं है, लेकिन मंत्री जी जरूर जवाब देंगे सर, हाऊस को शायद यह पता है कि एक साल पहले सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी CARGIL ने फोर्सी किया कि भारत सरकार is going to import one million tonne. जुलाई में कारगिल का बयान आ गया था। मैं यह जानना चाहती हूँ, जो मंत्री जी से संबंधित है, कि किस भाव पर व्हीट इम्पोर्ट हो रहा है? हमारे हिंदुस्तान के किसानों को MSP के तहत व्हीट का जो भाव दिया जाता है और जो फॉरिन ट्रेडर्स को, विदेशी व्यापारियों को भाव दिया जाएगा, उसमें क्या अंतर है और इस अंतर के बारे में सरकार का क्या जवाब है?

श्री शरद पवार: सर, वैसे एक बात है कि जो इम्पोर्ट किया गया है, वह इंपोर्ट सिर्फ देश के सदर्न स्टेट्स के लिए किया गया है। जो माल आने वाला है, वह केरल में आएगा, कर्नाटक में आएगा, तमिलनाडु में आएगा, आंध्र प्रदेश में आएगा। इसकी कीमत क्या रहेगी, सारे डिटेल्स आने के बाद इसका अंदाजा एक दो दिन में हमारे पास आएगा। एक बात साफ है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से गेहूं प्रोक्योर करने के बाद जब केरल जाता है या तमिलनाडु जाता है, तो इसकी जो कीमत है, इसकी जो लागत आती है, इससे इम्पोर्टेड प्राइस वहां आने के बाद कम हो जाएगी।

श्री सभापति: श्री दीपांकर मुखर्जी। ...(**व्यवधान**)...आप बैठिए, बैठिए। दीपांकर मुखर्जी। Please take your seat मैं एलाऊ नहीं कर रहा। Nothing will go on record ...

(व्यवधान)... आप बैठिए, बैठिए। सरदार जी, बैठिए अभी। ...(व्यवधान)... आप बैठिए। यूं मत करिए। पहले जिनका क्वैश्चन है, पहले उनको पूछने दें। अगर आपको इतनी चिंता होती, तो आपकी तरफ से नहीं क्वैश्चन आ जाता?

श्रीमती वृंदा कारत: सर चिंता सबकी है।

श्री सभापति: वह ठीक है। बोलिए, दीपांकर जी।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I do not think any one will disagree with me on this question. Even the hon. Minister also will not disagree with me on this question, irrespective of whatever reply he has given that this is a case of mismanagement of food. मेरे ख्याल से इसमें कोई दोहरी राय तो नहीं है। मैं मिलियन टन्स में नहीं जाता हूँ। सर, आपने कहा है कि भंडार खाली करने को आपका इरादा था। बहुत अच्छा इरादा था। भंडार ऐसा आपने खाली किया, कि आपको एक्सपोर्ट करना पड़ा। what is this *bhandar khali karna?*

श्री सभापति: आप क्वैश्चन पर आइए।

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, यही तो मुद्दा है। The issue before the House is हम भंडार खाली करना चाहते थे, ...(व्यवधान)... मुझे तो बोलने दीजिए, भंडार खाली करना चाहते थे, तो यह भंडार आपका पीडीएस में नहीं गया, आपका भंडार गया एक्सपोर्ट करने के लिए, जुलाई, 2005 तक एक्सपोर्ट करते रहे। उसके बाद अचानक हमको यह ख्याल आ गया कि अब इम्पोर्ट करो। अब आप यह भी नहीं बोल रहे हैं कि कितने पैसे से एक्सपोर्ट करेंगे और कितने पैसे से हम किसान से लेंगे? Who are those responsible for the total mismanagement of food position and food allocation in this country, leading to a position where the *bhandar* has to be made *khali* so that import is done? This is my first question. There has to be a specific assurance that whatever cost you are incurring on importing the foodgrains will not be more than the ruling price which you are going to give to the farmers. This is the assurance we want to have from him.

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है। बैठिए।

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, the simple thing is, जहां तक भंडार खाली करने की बात है, जो अभी हुई, यह बात सच है कि इस देश में नुकसान सहन करके एक्सपोर्ट करने का डिसिजन भारत सरकार ने लिया था, मगर यू॰पी॰ए॰ सरकार ने आने के बाद वह डिसिजन कैंसिल

किया, रद्द किया। इस सरकार ने आने के बाद गेहूं के एक्सपोर्ट का जो कार्यक्रम था, उसे 100 प्रतिशत, पूरा बंद किया। हमने कभी एक्सपोर्ट करने के लिए इजाजत नहीं दी। ...(व्यवधान)....

श्री दीपांकर मुखर्जी: जुलाई, 2004 तक क्या एक्सपोर्ट हुआ, सर? मेरे ख्याल से इस पूरे मामले की एक इंक्वायरी की जानी चाहिए। ...(**व्यवधान**)... There must be an inquiry into the wholething ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: आप बैठिए। यूं ही इंक्वायरी नहीं होती। पहले क्वेश्चन का उत्तर तो सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद पवार: सर, सिम्पल बात यह है, जैसा मैंने कहा कि डा॰ मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद गेहूं एक्सपोर्ट करने का जो पहले का डिसिजन था, वह रद्द मतलब कैंसिल किया गया।

श्री दिग्विजय सिंह: मनमोहन सिंह जी की सरकार के आने के बाद कब किया गया? ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद पवार: इस सरकार ने एक्सपोर्ट करने की इजाजत किसी को नहीं दी। Practically, there is no export up to August, 2004. No export up to 2004. अगस्त, 2004 तक जो एक्सपोर्ट हुआ, इसका आर्डर पिछली सरकार के समय में दिया गया था, इस सरकार ने एक किलो गेहूं भी एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर नहीं दिया। जहां तक एक्सपोर्ट करने का ...(**व्यवधान**)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: क्वालिटी खराब हो गई और ...(**व्यवधान**)...

SHRI SHARAD PAWAR: Please allow me to speak. सुनिए तो। तब जो टोटल स्टॉक की स्थिति थी, उस स्थिति में वे अगर स्टॉक को कम करने के लिए कदम नहीं उठाते तो गलत होता, गेहूं का नुकसान होता, उसकी क्वालिटी खराब होती, इसलिए जो कुछ कदम उठाए गए, वे तब भी राष्ट्र के हित में उठाए गए, इस बारे में मेरी कोई दो राय नहीं हैं। मगर, एक बात है कि जब अपनी बफर स्टॉफ की सिचुएशन खराब हो, तब रिस्क नहीं लेना चाहिए और इसलिए खाली 5 लाख टन इम्पोर्ट करने का डिसिजन लिया गया है, यानी दो हफ्ते की जो जरूरत है, उससे कम इम्पोर्ट करने का डिसिजन लिया गया है।

जहां तक प्रिक्योरमेंट की बात है, पिछले साल देश के टोटल प्रोडक्शन पर असर पड़ा था, खास तौर पर गेहूं पर और प्रोडक्शन का रिफ्लेक्शन प्रिक्योरमेंट पर होता है। इस साल प्रोडक्शन बढ़ा है

और अंदाज़ा है कि यदि इस साल प्रोडक्शन अच्छा हो गया, तो प्रिक्योरमेंट भी बढ़ जाएगा।

श्रीमती वृंदा कारत: सर, मंत्री जी ने सही जवाब नहीं दिया, 19 मिलियन टन ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप जो चाहें, वह जवाब दिलवाने के लिए मैं मंत्री जी पर दबाव नहीं डाल सकता।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, पहले तो मैं आपकी टिप्पणी के उत्तर में बताना चाहूंगी कि यह चिंता सबकी है, पूरे सदन की है।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है, वह बात हो गई।

श्रीमती सुषमा स्वराज: हम सबने सवाल भेजे थे, लेकिन चूंकि लॉटरी में तो किसी एक सदस्य की ही सवाल निकलता है, वह उनका निकला, वरना सवाल सबके गए हुए थे।

श्री सभापति: चलिए, अब आप सप्लिमेंट्री क्वेश्चन करिए।

श्री मूलचंद मीणा: आपको सप्लिमेंट्री क्वेश्चन करने के लिए वक्त दिया गया है, सप्लिमेंट्री क्वेश्चन करिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो चुका हो और आपके कहे मुताबिक जिस देश के भंडार भरे हों, वहां गेहूं का आयात करना पड़े। मंत्री जी, मैं आपसे दो बातें जानना चाहती हूं। आपने प्रारम्भ में कहा कि बफर स्टॉक के मानदंड के अनुसार बफर स्टॉक में कमी है। प्रश्न के 'क' भाग के रूप में आप यह बताइए कि हमारे यहां बफर का मानदंड क्या है और हमारा स्टॉक कितना कम है? इसी के साथ ही साथ प्रश्न के 'ख' भाग के रूप में मैं यह पूछना चाहती हूं कि आप कितने मूल्य का आयात कर रहे हैं, आपका अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है और उससे आयातित मूल्य कितना कम या ज्यादा है?

उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह): सभापति महोदय, हर तिमाही का बफर स्टॉक अलग-अलग होता है और 1 अप्रैल को ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मानदंड तो अलग नहीं हो सकता।

श्री सभापति: आप मंत्री जी को बोलने दीजिए।

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: हर समय अलग-अलग होता है। 1 अप्रैल को 40 लाख टन बफर

स्टॉक निर्धारित किया गया, जो रहना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोगों के पास 20.12 लाख टन की कमी 1अप्रैल को रह जाती है।

श्री दीपांकर मुखर्जी: 40 से 20 क्यों हुआ? ...(**व्यवधान**)...

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: पिछली बार प्रिक्योरमेंट में कमी थी ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, बफर का मानदंड तिमाही-तिमाही तय कैसे हो सकता है? स्टॉक तो तिमाही-तिमाही तय हो सकता है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: मंत्री जी क्वेश्चन का जो जवाब दे रहे हैं, उसे सुन लीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, स्टॉक तो तिमाही तय हो सकता है कि हमारे पास यह स्टॉक है, लेकिन मानदंड तो एक ही होगा कि इतना बफर चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप सुनिए मंत्री जी को।

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: एक जुलाई को 131 लाख टन, एक अप्रैल को 37 लाख टन और 1 अक्तूबर को 161 लाख टन, यह गेहूं के लिए बफर नॉर्म्स हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: यह स्टॉक है या मानदंड है? मानदंड तो एक ही रहेगा ना।

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: यह स्टॉक है। मानदंड कभी एक-सा नहीं रहता है, वह हर तिमाही पर बदलता रहता है ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: क्यों? मानदंड कैसे बदल सकता है ...(**व्यवधान**)...।

श्री सभापति: आप पहले सुन लीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद पवार: हर तिमाही पर मानदंड अलग रहता है क्योंकि यह खपत के हिसाब से निर्धारित होता है साथ ही साथ यह प्रोक्योरमेंट के समय के आधार पर भी निर्धारित होता है। जहां तक मानदंड की बात है, एक अप्रैल को मानदंड 40 लाख टन होता है, एक जुलाई को 171 लाख टन का होता है, एक अक्तूबर को 110 लाख टन का होता है और एक जनवरी को 82 लाख टन का होता है।

राज्य मंत्री जी ने अभी जो इन्फॉर्मेशन दी, यह उन्होंने अप्रैल के बारे में बताई। अप्रैल में सिचुएशन यह होती है कि प्रैक्टिकली स्टॉक पूरा खत्म हो जाता है और नया प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाता है। जब नया प्रोक्योरमेंट शुरू होने का समय आता है, तब ज्यादा स्टॉक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारे यहां अनुभव यह है कि 15 अप्रैल से आम तौर पर हमारी जो प्रोक्योरमेंट होती

है, उस समय प्रतिदिन एक मिलियन टन के आस-पास खरीद होती है। यही कारण है कि अप्रैल में ज्यादा स्टॉक की आवश्यकता नहीं होती और इसलिए अप्रैल का मानदंड कम है, वह केवल 40 लाख टन है। इस वर्ष यह 40 लाख टन से भी कम हो गया और इसलिए यह कदम उठाया गया ...(व्यवधान)..दूसरा इसमें ...(व्यवधान)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Correct, that is the point, Sir, why it has been allowed ....(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please don't disturb ....(*Interruptions*)... Please don't disturb. I won't allow you ....(*Interruptions*)... I wan't allow you. Please take your seat. ....(*Interruptions*)... Please take your seat. Let him speak. ....(*Interruptions*)...

श्रीमती वृन्दा कारत: सर मुख्य सवाल तो किसानों का है। प्रोक्योरमेंट के बारे में मिनिस्टर साहब कोई आश्वासन दें ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: वह बात तो ठीक है, लेकिन पहले आप उन्हें बोलने दीजिए।

श्री शरद पवार: जो टोटल ऑफ टेक है, देश में जो टोटल बंटवारा होता है, 2001-2002 में वह 120 लाख टन होता था, जो 2002-2003 में 203 लाख टन हो गया और इस साल वह 242 लाख टन This means, the total distribution of the food and the allocation of food has been practically doubled in the last two years. And that is one of the major reasons why it has affected the stock.

MR. CHAIRMAN: Shri M.S. Gill. ....(*Interruptions*)... Shri M.S. Gill. ....(*Interruptions*)...

श्रीमती वृन्दा कारत: सर मेरे पास इसके आकड़े हैं और जो आकड़े अभी दिए गए हैं वे इससे मैच नहीं करते ...(व्यवधान)..

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, मेरे सवाल का तो आधा ही जवाब आया है, कीमत के बारे में इन्होंने जवाब नहीं दिया है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। आपने अपना क्वेश्चन कर लिया है और अगर आप क्वेश्चन के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो रूल्स के अन्दर जो दूसरी व्यवस्था है, आप उसका उपयोग कीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, मेरे सवाल का केवल आधा ही जवाब आया है। जितने पर आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, वह कीमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कितनी कम या ज्यादा है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अब आप श्री एम॰ एस॰ गिल जी को सवाल पूछने दीजिए ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: सर, यह क्या हो रहा है?

श्री सभापति: गेहूं का आयात हो रहा है, और क्या हो रहा है ...(व्यवधान)...

श्री एम.एस.गिल: हमें भी सुन लीजिए।

सर, यह मामला बहुत ही गम्भीर है। वर्ष 2000 से 2005 तक के समय में कुल 3.5 करोड़ टन के अन्दर 1.3 करोड़ टन गेहूं और 1.7 करोड़ टन के लगभग चावल एक्सपोर्ट हुआ। ये आपके ही आंकड़े हैं।

बफर स्टॉक की जो पोज़ीशन है, उसके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन अभी उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। फिर कभी जब डिस्कशन होगी, तब इसके बारे में बात करेंगे। सवाल यह है, कि आपके उत्तर में ए, बी, सी के अन्दर सारा फोकस कन्ज्यूमर के ऊपर और उसके लिए अनाज की व्यवस्था करने के ऊपर है। इसके घटने की वजह यह है कि पहले तो हमने इसका एक्सपोर्ट किया, और फिर हमने देखा कि, मार्केट प्राइज़िज बढ़ गए, वह क्यों बढ़े? इसके उत्तर में कहा गया कि प्रोक्योरमेंट पूरी नहीं हुई और जब यह पूछा गया कि क्यों पूरी नहीं हुई 1.6 per cent, not even half or less than half of even our official inflation is the price-rise we give every year for the last three-four years for wheat or rice in Punjab or anywhere. टाइमिंग की भी अब बात है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पांच लाख टन आएगा, चलो हो सकता है कि चेन्नई में वह आएगा। और आप कहते हैं कि वहां पड़ी रहेगी। हमने कल भी यह उठाया था और प्रधान मंत्री जी ने भी जवाब दिया। लेकिन इसका इफेक्ट सारे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यू॰पी॰, गंगानगर सब के ऊपर होगा क्योंकि उनकी फसल आ रही है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्रश्न कर लीजिए, प्लीज।

श्री एम॰एस॰गिल : तो मंत्री जी, किसान का और उसका क्या बंदोबस्त करेंगे, उसके ऊपर वे दुखी हैं। मंत्री जी, उसका कुछ बताएंगे?

श्री शरद पवार : महोदय, यह सिम्पल बात है, जो मिनिमम प्राइस तय की है वह सपोर्ट प्राइस से वहां गेहूं का प्रोक्योरमेंट हो जाएगा ओर इसलिए जो किसान को मिलने वाली कीमत है वह उनको दी जाएगी, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी।

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा: महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर गेहूं के स्टॉक में कमी आ रही है या प्रोडक्शन में कमी आ रही है तो डायवर्सिफिकेशन पर जोर क्यों दिया जा रहा है। करोड़ों, अरबों रुपए के इश्तहार टी॰वी॰ में और अखबारों में दिए जाते हैं, जो गेहूं और चावल है उसकी उपज कम करो। वैसे इसका रिजल्ट तो यही होना ही था। क्या कारण है क्यों कम किया जा रहा है मैं यह पूछना चाहता हूं तथा यह डायवर्सिफिकेशन क्यों है?

श्री शरद पवार: महोदय, खास तौर पर पंजाब और हरियाणा में पिछले कई सालों से गेहूं और चावल, इसका रोटेशन हो रहा है। गेहूं और चावल की लगातार क्रॉप लेने के बाद जमीन पर कोई असर हो रहा है। साथ-साथ वहां का जो वाटर लेवल है, इस पर भी असर हो रहा है। इसलिए पंजाब सरकार की यह जो सूचना थी और भारत सरकार ने भी इस पर एक्सपर्ट कमेटी अपोइंट की थी और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उनसे यह सलाह मिली हे कि यहां जो रोटेशन है कंटीन्यूसली गेहूं-राइस, गेहूं-राइस, तो इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है, डायवर्सिफिकेशन करने की आवश्यकता है। यदि नहीं करेंगे तो जमीन की क्वालिटी पर असर हो जाएगा और देश का भंडार जहां होता है वहां की जमीन की क्वालिटी पर असर हो जाएगा, तो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है और साथ-साथ पंजाब और हरियाणा में जा वाटर लेवल है, इसमें जो असर हो रहा है वह नजर-अंदाज नहीं कर सकते। इसलिए डायवर्सन की वहां आवश्यकता है। इसलिए भारत सरकार भी इसमें सोच रही है, एन्करेज कर रही है।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, wheat is being imported through the southern ports. Export or import of foodgrains has an impact on the country. I would like to know from the hon. Minister what will be the impact on farmers and agriculture, as far as the southern States are concerned, by virtue of this import.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, this entire material will land ultimately at Cochin, Mangalore and Tuticorin. This entire region does not produce wheat at all.

श्री दिग्विजय सिंह: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अखबारों में यह खबर छप रही है कि जब आप यह माल देश में लाएंगे उसी समय हमारा भी माल तैयार हो जाएगा। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जिस बफर स्टॉक की आपको इतनी चिंता है, यह उस समय क्यों लाया जा रहा है जब हमारा माल तैयार हो जाएगा?

श्री शरद पवार: जब हमारा माल तैयार हो जाएगा वह एसेंशियली नॉर्दन इंडिया में तैयार हो जाएगा जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जिस पर सरकार परचेज़ करने करने वाली है, इसमें कोई असर होने वाला नहीं है, वह कीमत देने की कमिटमेंट भारत सरकार की है, भले ही कीमत नीचे जाए तो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर हम परचेज़ करेंगे और जितना मिलेगा वह हम परचेज़ करेंगे।

**102. [The questioner (Shri B.J. Panda) was absent. For answer vide page 36.]*

**103. [The questioner (Shri Raj Kumar Dhoot) was absent. For answer vide page 37.]*

रेल दुर्घटनाएं

*104. **श्री मोती लाल वोरा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्ष में कितनी रेल दुर्घटनाएं जनता की सूझबूझ और सक्रियता के कारण टल गई;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्होंने इन दुर्घटनाओं को रोकने में सहयोग किया;

(ग) सरकार ने इन लोगों को क्या पुरस्कार प्रदान किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलू): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले दो वर्ष में (2004-05 और चालू वर्ष 2005-06 में आज तक) सचेत जनता द्वारा दस दुर्घटनाओं का टाला गया।

(ख) और (ग) इन व्यक्तियों तथा उन्हें प्रदान किए गए पुरस्कारों का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:

क्र. सं.	नाम और पता	रोकी गई दुर्घटना का ब्यौरा	क्षेत्रीय रेलवे	रेलवे द्वारा पुरस्कार का ब्यौरा
1.	श्रीमती अमला मेरी, कालकुलम, कन्याकुमारी और श्री देवराजन पट्टावलै, कन्याकुमारी (तमिलनाडु)	09.07.04 को रेलपथ पर गिरे मलवे को देखा तथा 371 पैसेंजर के ड्राइवर को सचेत किया।	दक्षिण	प्रत्येक को 2500/- का नकद पुरस्कार
2	श्री भाऊलाल राधाजी दियोरे और हरी चंद्र राधाजी दियोरे, ग्राम: साईगांव, ता. यिओला, जिला नासिक, महाराष्ट्र	03.05.2005 को वेल्डन की टूटफूट को देखा और 591 पैसेंजर गाड़ी को रुकवा दिया।	दक्षिण मध्य	प्रत्येक को 2500/- रुपये का नकद पुरस्कार और प्रशास्ति पत्र